

प्रेषक,

सुभाष कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 25 सितम्बर, 2009

विषय:-मुख्य राजस्व आयुक्त/अपर मुख्य राजस्व आयुक्त के न्यायालयों में राजस्व अधिवक्ताओं के पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-1989/XXXI-रीडर-2007-08 दिनांक 05 मार्च, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व न्यायालयों में योजित वादों की प्रभावी पैरवी किये जाने के दृष्टिगत मुख्य राजस्व आयुक्त, न्यायालय, देहरादून हेतु एक पद, अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, न्यायालय, देहरादून हेतु एक पद, सर्किट कोर्ट नैनीताल एवं सर्किट कोर्ट पौड़ी हेतु एक-एक पद अर्थात् कुल चार राजस्व अधिवक्ताओं के पद सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने हैं।

2- राजस्व अधिवक्ता के सृजित पदों पर राजस्व अधिवक्ता को चयनोपरान्त निम्न प्रकार फीस देय होगी:-

(1) रिटेनरफीस रू0 3000.00 (रू0 तीन हजार मात्र) प्रतिमाह।

(2) बहस हेतु रू0 750.00 (रू0 सात सौ पचास मात्र) प्रति कार्य दिवस।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व अधिवक्ताओं का चयन एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड, सचिव न्याय, आयुक्त गढ़वाल मण्डल/आयुक्त कुमाऊँ मण्डल होंगे। राजस्व अधिवक्ता के पद पर आबद्धता के लिए आवेदक को विधि व्यवसाय में कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना एवं राजस्व मामलों का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। चयनोपरान्त राजस्व अधिवक्ता के पद पर आबद्धता की अविध एक वर्ष के लिए होगी। उक्त प्रकार से आबद्ध राजस्व अधिवक्ताओं का कार्यकाल उनके कार्य एवं आचरण के आधार पर प्रत्येक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा, किन्तु इनकी अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष से अधिक नहीं होगी। राजस्व अधिवक्ताओं के चयन की प्रक्रिया प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी एवं राजस्व अधिवक्ताओं के आबन्धन आदेश/कार्यकाल बढ़ाये जाने के परिप्रेक्ष्य में नवीनीकरण आदेश न्याय विभाग द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

4- आबद्ध किये गये राजस्व अधिवक्ताओं की रिटेनर फीस एवं बहस हेतु फीस पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-06 के अधीन लेखाशीर्षक-2029-भू-

राजस्व-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-राजस्व आयुक्त अधिष्ठान के अन्तर्गत मद संख्या-16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या-337NP/XXVII(5)/09 दिनांक 15 सितम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-457 (1)/XVIII(1)/2009 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराँय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव न्याय, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) उत्तराखण्ड।
9. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त विभाग (अनुभाग-3 एवं 7), उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)  
अनुसचिव।